



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22383

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 2649 सन् 2026

मंजू सिंह एवं 2 अन्यआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊविरोधी पक्षकार

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : विकास चंद्र द्विवेदी, अनूप कुमार सिंह

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायामूर्ति श्री प्रकाश सिंह

विरोधी पक्षकार संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनय मिश्रा द्वारा दायर वकालतनामा को अभिलेख पर ले लिया गया है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस आवेदन के माध्यम से, आवेदकों ने दिनांक 28-04-2014 की आरोपपत्र और दिनांक 05.08.2014 के समन आदेश (अनुलग्नक संख्या 2 में निहित) के साथ-साथ विशेष सत्र परीक्षण (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम) संख्या 450/2017 की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की है, जो वाद संख्या 451/2013, धारा 323, 504, भारतीय दण्ड संहिता और धारा 3(1)X अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना मॉल, जिला लखनऊ, माननीय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम, जिला लखनऊ के न्यायालय में लंबित है [राज्य बनाम मंजू सिंह और अन्य], दिनांक 04-12-2025 को पक्षों के बीच हुए विवाद के सौहार्दपूर्ण निपटारे के आधार पर।

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ भ्रम के कारण यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी और ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद दोनों पक्ष आपस में मिले और उन्होंने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने विवादों को सुलझा लिया, जिसे 4.12.2025 को लिखित रूप में दर्ज कर लिया गया है। अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अब दोनों पक्षों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने सभी विवादों को समाप्त कर दिया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आगे की आपराधिक कार्यवाही व्यर्थ होगी और याचिकाकर्ताओं को परेशान करने के समान होगी।

अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने यह भी निवेदन किया कि इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 6.1.2026 के आदेश द्वारा धारा 482 संख्या 10966/2025 के अंतर्गत दायर आवेदन में समझौते के सत्यापन के लिए मामले को संदर्भित किया था और उक्त आदेश के अनुपालन में, दोनों पक्ष अधीनस्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे और दिनांक 4.12.2025 के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समझौते के दस्तावेज का सभी संबंधित पक्षों की उपस्थिति में सत्यापन किया गया था और सत्यापन का आदेश दिनांक 16.1.2026 को पारित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अब मामले में पक्षों के बीच समझौता हो चुका है, और अतः उपरोक्त मामले की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान आवेदकों का मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2021, एससीसी ऑनलाइन एससी 966** मामले में दिए गए निर्णय के अनुपात के पूर्णतः अनुरूप है और उन्होंने अनुच्छेद संख्या 9, 10, 11 और 16 का भी उल्लेख किया है, जो नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

“9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद, हमारा मत है कि इस अपील में हमारे विचार के लिए दो प्रश्न हैं। पहला, क्या संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग 'गैर-समझौता योग्य अपराध' से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही रद्द करने की शक्ति को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम जैसे विशेष कानूनों से उत्पन्न अपराधों तक बढ़ाया जा सकता है?

10. जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, रामगोपाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के हालिया निर्णय का सीधा उल्लेख करना अनुचित होगा, जिसमें हम दोनों न्यायाधीशों (माननीय एन.वी. रमना, मुख्य न्यायाधीश और माननीय सूर्यकांत, न्यायमूर्ति) की दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक समान प्रश्न था। सकारात्मक उत्तर देते हुए, यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत इस न्यायालय में निहित अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के विरुद्ध निषेध के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध है। आगे यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 142 या धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने का मानदंड पूर्ण न्याय करना होगा। इसलिए, यह न्यायालय या उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, अपराध की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़ित/ शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से समझौता कर लिया है, अपनी-अपनी संवैधानिक/ अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द कर सकता है।

11. रामगोपाल (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने आगे यह प्रतिपादित किया कि गैर-जघन्य अपराधों या मुख्य रूप से निजी प्रकृति के अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को अपील स्तर सहित कार्यवाही के किसी भी चरण में रद्द किया जा सकता है। हालांकि, न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि बेईमान अपराधी क्रूर बल, धमकियों, रिश्वत या अन्य ऐसे अनैतिक और अवैध साधनों के माध्यम से समझौता करके अपने आपराधिक दायित्वों से बचने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए न्यायालय ने चेतावनी दी कि जिन मामलों में दोषसिद्धि के बाद समझौता होता है, उनमें न्यायालयों को, अन्य बातों के अलावा, समझौते के तरीके के साथ-साथ संबंधित घटना से पहले और बाद में आरोपी के आचरण की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए। निष्कर्ष निकालते हुए, न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश भी तैयार किए और कहा:

“19 फिर भी, हम दोहराते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संदर्भ में व्यापक शक्तियों का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए: (i) अपराध की प्रकृति और समाज की चेतना पर उसका प्रभाव; (ii) यदि कोई चोट है तो

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उसकी गंभीरता; (iii) आरोपी और पीड़ित के बीच समझौते की स्वैच्छिक प्रकृति; और (iv) कथित अपराध के घटित होने से पहले और बाद में आरोपी व्यक्तियों का आचरण और/या अन्य प्रासंगिक विचार।” [ज़ोर दिया गया]

16. दूसरी ओर, यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन अपराध, यद्यपि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत आता है, मूलतः निजी या दीवानी प्रकृति का है, या जहाँ कथित अपराध पीड़ित की जाति के कारण नहीं किया गया है, या जहाँ कानूनी कार्यवाही जारी रखना विधि का दुरुपयोग होगा, तो न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार, जब किसी समझौते के आधार पर कार्यवाही रद्द करने की प्रार्थना पर विचार किया जाता है, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि यदि विचाराधीन अपराध बिना दण्ड के रह जाता है, तब भी अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन या उसमें कमी नहीं आएगी, तो मात्र इस तथ्य से कि अपराध किसी ‘विशेष कानून’ के अंतर्गत आता है, यह न्यायालय या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा।”

दूसरी ओर, विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदकों के पक्ष का समर्थन किया है और उनका कहना है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और अब दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है, इसलिए आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त दलीलों पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलीलों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षकारों के बीच 4.12.2025 को समझौता हुआ था और उक्त समझौते का सत्यापन 16.1.2026 को किया गया था और अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के बयान के अनुसार, वे उपरोक्त मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

उपरोक्त को देखते हुए, चूंकि आवेदकों और विरोधी पक्षकारों ने 4.12.2026 को समझौता कर लिया है और अब कोई विवाद शेष नहीं है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003) 4 एससीसी 675**; **निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो [2008] 9 एससीसी 677**; **मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य (2008) 16 एससीसी 1**; **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303**; और **नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466** में दिए गए निर्णयों के मद्देनजर उपर्युक्त आपराधिक मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

परिणामस्वरूप, विशेष सत्र परीक्षण (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम) संख्या 450/2017 में आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही, केस अपराध संख्या 451/2013 के संबंध में, धारा 323, 504, भारतीय दण्ड संहिता और धारा 3(1)X अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना मॉल, जिला लखनऊ के अंतर्गत, एतद्वारा रद्द की जाती है।

समझौता पत्र इस आदेश का हिस्सा होगा।

इसके परिणामस्वरूप परिणाम भुगतने होंगे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदन को तदनुसार स्वीकार कर लिया गया है।

मार्च 31, 2026

राम मूर्ति

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।